आकाशवाणी देहरादून (उत्तराखण्ड)

मंगलवार 31.03.2026 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- ऋषिकेश बाईपास के फोर–लेन निर्माण के लिए केंद्र से एक हजार 105 करोड़ रुपए मंजूर। लगभग 12 किलोमीटर लंबा बाईपास भट्टोवाला और ढालवाला गांवों से होकर गुजरेगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत में निर्माणाधीन अत्याधुनिक साइंस सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। कहा– यह विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का बनेगा प्रमुख केंद्र बनेगा।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा– प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति। किसी भी जिले में किल्लत नहीं।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने देहरादून शहर में कानून व्यवस्था को लेकर गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

केंद्र / मंजूरी

ऋषिकेश बाईपास के फोर–लेन निर्माण कार्य के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से बड़ी स्वीकृति प्राप्त हुई है। मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए एक हजार 105 करोड़ रुपए से अधिक की तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। यह बहुप्रतीक्षित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग–सात पर तीनपानी फ्लाईओवर से लेकर खारास्रोत पुल तक विकसित की जाएगी। लगभग 12 किलोमीटर लंबा यह बाईपास भट्टोवाला और ढालवाला गांवों से होकर गुजरेगा। परियोजना को तीन वर्षों की समयावधि में पूरा किया जाएगा और कार्य में किसी प्रकार की लागत या समय वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाएं ई–टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी और सभी कार्य निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने से ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी, जाम की समस्या में कमी आएगी और राज्य के आर्थिक और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, राज्य के दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चम्पावत जिले के भ्रमण के दौरान लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अत्याधुनिक साइंस सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्धता का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित वैज्ञानिक गैलरियों और चार मंजिला साइंस कैंपस सुविधा का अवलोकन किया। इस कैंपस में 40 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर औरअन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे यह केंद्र विद्यार्थियों के लिए आवासीय वैज्ञानिक शिक्षण का भी महत्वपूर्ण स्थल बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडलों को देखा और नन्हें वैज्ञानिकों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि यह साइंस सेंटर, भविष्य में प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस केंद्र के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और खगोल विज्ञान को समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था

को निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मानकों और श्रमिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने पर भी बल दिया।

फायर सीजन

प्रदेश में फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। हर साल गर्मियों में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वन संपदा, वन्यजीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इसे देखते हुए इस बार विभाग ने पहले से ही रणनीति तैयार कर ली है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य के संवेदनशील वन क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग ने फायर वॉचर्स की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों और वन पंचायतों को भी वनाग्नि को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें आधुनिक उपकरणों से लैस हैं और कंट्रोल रूम को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से भी जंगलों में आग की घटनाओं पर नजर रखने की व्यवस्था की गई है। वन अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सभी डिवीजनों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंनें कहा कि जंगलों में आग की घटनाओं को न्यूनतम करने और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रयासरत है।

खाद्य आपूर्ति मंत्री

प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और किसी भी जिले में किल्लत जैसी स्थिति नहीं है। यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानभवन एलपीजी की मांग और आपूर्ति को लेकर पूरे प्रदेश की समीक्षा करने के बाद कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दैनिक रूप से पर्याप्त आपूर्ति पहुंच रही है और घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी में कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से कहा कि किसी भी सूरत में गैस एजेंसी या स्टोर रूम से सिलेंडर न दिए जाएं, बल्कि सभी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। श्रीमती आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी से कड़ाई से निपट रही है। अभी तक प्रदेश में 173 जगह छापेमारी की गई है और 15 प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आज सचिवालय में देहरादून शहर में कानून व्यवस्था को लेकर गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रोड–रेज और हुड़दंग की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने देहरादून शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने और दिन–रात गस्त के साथ ही सुबह भी गश्त बढाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बार और रेस्टोरेंट को निर्धारित समय पर बंद करने पर सख्ती बरती जाए। साथ ही बार संचालकों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए। मुख्य सचिव ने नियमों का पालन न करने वाले बार और अवैध बार संचालकों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से न करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हुड़दंगियों की पहचान के लिए किरायेदारों और पी.जी में रहने वालों का भी सघन सत्यापन अभियान चलाने पर जोर दिया।

नीति आयोग

अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी से आज जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कसार देवी में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने उपाध्यक्ष को जिले की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्वच्छता, ग्राम्य विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जिले में संचालित विकासात्मक योजनाओं, उपलब्धियों और चुनौतियों से भी उपाध्यक्ष को अवगत कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने श्री बेरी को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाद्रि हैंडलूम से निर्मित शॉल और अन्य पहाड़ी उत्पाद भेंट किए। उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छ वातावरण की सराहना की।

एंटी ड्रग यूनिट

पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज राजकीय इंटर कॉलेज, पौड़ी नगर में नशा–विरोधी इकाई का गठन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक करते हुए समाज में नशा उन्मूलन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम ने नशा–विरोधी इकाई के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और समाज में जागरुकता लाना है। उन्होंने बताया कि यह इकाई विद्यालय स्तर पर एक सक्रिय जागरूकता और निगरानी समूह के रूप में कार्य करेगी, जिसमें छात्र–छात्राएं और शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके माध्यम से समय–समय पर जागरूकता रैलियां, गोष्ठियां, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।